



मुगल साम्राज्य का पतन और अठारहवीं शताब्दी सम्बन्धी वाद-विवाद : राजस्थान के विशेष सन्दर्भ में

नरेश कुमार

शोधार्थी, इतिहास विभाग

महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक

सारांश

भारतीय इतिहास में अठारहवीं शताब्दी का काल एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जीवंत और कँपकँपी सी पैदा कर देने वाला विषय है जो अपने विरोधाभासितापूर्ण चरित्र को लेकर लम्बे समय से इतिहासकारों के बीच विवाद का विषय बना हुआ है। महान मुगल साम्राज्य जो लगभग 150 वर्षों से सम्पूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप पर प्रभावशाली ढंग से अपना नियन्त्रण स्थापित किए हुए था, का पतन अथवा राजनीतिक बिखराव इस शताब्दी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है। इस घटना ने इतिहासकारों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और उनके मध्य मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों को लेकर एक बहस की शुरुआत हो गई। ये वो काल था जिसमें बहुत कुछ नष्ट हो रहा था तो बहुत कुछ निर्मित हो रहा था। बहुत कुछ विस्थापित हो रहा था तो बहुत कुछ प्रतिस्थापित हो रहा था। इसमें बहुत कुछ अच्छे के लिए घटित हो रहा था तो बहुत कुछ बुरे के लिए घटित हो रहा था। इसलिए ये शताब्दी इतिहासकारों के शोध के लिए एक स्वपनिल शताब्दी बनी हुई है। प्रस्तुत शोध पत्र में मुगल साम्राज्य के पतन और अठारहवीं शताब्दी सम्बन्धी वाद-विवाद को राजस्थान के विशेष सन्दर्भ में समझने का प्रयास किया गया है।

संकेत शब्द :- अठारहवीं शताब्दी, मुगल साम्राज्य, जागीरदारी संकट, कृषि संकट, व्यापारिक पूँजी, जागीर, व्यापार और वाणिज्य

मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में इतिहासकार स्पष्ट रूप से दो खेमों में विभाजित नजर आते हैं। इतिहासकारों के एक समूह के अनुसार मुगल साम्राज्य के राजनीतिक पतन के साथ ही सामाजिक और आर्थिक पतन की प्रक्रिया आरम्भ हो गई थी। जबकि इतिहासकारों का दूसरा समूह अठारहवीं शताब्दी को इसके स्वयं के आलोक में मुगल साम्राज्य के साथ से अलग करके इस राजनीतिक अव्यवस्था अथवा संकट को आर्थिक सम्पन्नता से प्रेरित क्षेत्रीय उभार अथवा दबाव के रूप में देखता है जिसमें आर्थिक पुनर्रचना शुरुआत हो गई थी। प्रो० सतीश चन्द्र और इरफान हबीब ने जागीरदारी संकट और कृषि संकट सम्बन्धी अवधारणा प्रस्तुत कर इस शताब्दी को आर्थिक संकट के दौर के रूप में प्रस्तुत किया है। सतीश चन्द्र ने जागीर और मनसब जैसी मुगल संस्थाओं की कार्यप्रणाली की कमी को उत्तर सतरहवीं सदी के वित्तीय संकट के लिए उत्तरदायी ठहराया।ⁱ बाद में उन्नीस सौ अस्सी के दशक में उन्होंने अपनी स्थिति में थोड़ा परिवर्तन किया और राजनीतिक-प्रशासनिक साम्राज्य के संकट के लिए आर्थिक पक्ष पर बल दिया। इस अवधारणा की पुष्टि करते हुए इरफान हबीब ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि मुगल साम्राज्य द्वारा राजस्व की ऊँची मांग के कारण किसानों ने बड़ी संख्या में कृषि का त्याग करके निष्क्रमण किया और व्यापक स्तर पर विद्रोह किए जिसके परिणामस्वरूप साम्राज्य का पूरा तंत्र चममरा गया और एक आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया।ⁱⁱ इस मत के विपरीत इतिहासकारों के दूसरे समूह ने मुगलों की कृषीय व्यवस्था एवम् राजस्व संग्रह की व्यवस्था के सीमित दायरे से बाहर निकल कर दूसरे प्रकार के गैर आर्थिक उत्पादनों को अपने शोध का आधार बनाया है। इनके अध्ययनों से एक तथ्य स्पष्टतः उभरता है कि राजनीतिक केन्द्रीयकृत नौकरशाही राज्य में राजनीतिक पतन के पश्चात भी सामाजिक एवम् आर्थिक विकास की प्रक्रिया जारी रही। अशिन दास गुप्ता की मान्यता इस बात की पुष्टि करती है कि संयुक्त व्यापारिक संस्थाएँ पतन के दौर में भी राजनीतिक सीमाओं के पार आवागमन, लेनदेन एवम् बीमा सेवाओं को जारी रखती है।

उनके अनुसार यूरोपीय व्यापार के प्रभाव के कारण हॉलाकि निर्यात व्यापार और सूत जैसे बन्दरगाही शहरों का पतन हुआ किन्तु इसके बावजूद आन्तरिक व्यापार में काफी बढ़ोतरी हुई।ⁱⁱⁱ बी० आर० ग्रोवर ने भी अठारहवीं शताब्दी में ग्रामीण व्यापार के उत्थान के बारे में लिखते हुए कहा है कि विदेशी आक्रमणों, यूरोपीय एवम् अंग्रेजों के मध्य प्रतिस्पर्धा एवम् मुगल अमीरों की बर्बादी के बावजूद भी स्थानीय ग्रामीण व्यापारिक उत्पादन ने उपमहाद्वीप में स्थित प्रान्तीय बाजारों में अपने लिए रास्ते ढूँढ लिये थे। इसके कारण दस्तकारी उद्योग से सम्बन्धित विदेशी व्यापार के नुकसान की क्षतिपूर्ति हो गई थी।^{iv} करेन लियोनार्ड के अनुसार भी व्यापारिक पूँजी का केन्द्र दिल्ली से हट कर प्रान्तीय केन्द्रों की ओर हो गया था। बड़े बैंकिंग फर्मों के व्यापार एवम् लेनदेन के व्यापार के स्थानान्तरण के साथ ही चलनशील व्यापारिक वर्ग का भी उत्थान हुआ जो व्यापार, अकाउन्टिंग एवं राजस्व संग्रह के काम में नियुक्त थे। इससे प्रान्तीय केन्द्रों पर व्यापारिक पूँजी के सक्रिय होने के संकेत मिलते हैं।^v सी० ए० बेली ने अपने ग्रन्थ रूलर्स, टाउन्समैन एवं बाजार्स में भी इसी प्रकार के तथ्य को उद्घाटित करते हुए बताया है कि मुगल सैनिक और वित्तीय संस्थाओं से शक्ति ग्रहण कर एक नवीन मध्यमवर्गीय वर्ग का उत्थान हुआ जिसने छोटे शहरों अथवा कस्बों में धन निवेश करना प्रारम्भ कर दिया। इससे व्यापार और वाणिज्य के विकास में सहायता मिली।^{vi} सी० ए० बेली ने सैनिक वित्तीयवाद सम्बन्धी अवधारणा भी प्रस्तुत की है। इससे उनका अभिप्राय है विशाल सेना रखना और उसको राजस्व संग्रहण में लगाना। इसके बावजूद बेली का मुख्य तर्क मध्यमवर्गीय वर्ग के उत्थान से है जो कि शाही शक्तियों से पूर्ण है। इन राजस्व संग्रहकों को सी० ए० बेली और संजय सुब्रमण्यम ने 'पोर्ट फोलियो पूंजीपति' कहकर पुकारा है।^{vii} अगर विगत कुछ वर्षों पूर्व की बात करें तो सामाजिक-आर्थिक पहलुओं के मद्देनजर रखते हुए क्षेत्रीय आधार पर ऐतिहासिक शोध कार्य को विशेष रूप से बढ़ावा मिला है। इस संदर्भ में राजस्थान भी इससे अछूता नहीं रहा और इतिहासकारों के शोध का आधार व उनके आकर्षण का केन्द्र बना रहा। सतीश चन्द्र, एस० पी० गुप्ता^{viii} और दिलबाग सिंह^{ix} ने जयपुर राज्य के संदर्भ में महत्वपूर्ण शोधकार्य किया तो वहीं मारवाड़ और भरतपुर राज्य जी० डी० शर्मा^x, बी० एल० भदानी^{xi} और आर० पी० राणा के अध्ययन का केन्द्र बिन्दु रहे। अगर अठारहवीं शताब्दी के राजस्थान के विषय में बात करें तो हम देखते हैं कि यहाँ व्यापार और वाणिज्य पूर्णतः विकसित अवस्था में था। एक तरफ तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद केन्द्रीय सत्ता कमजोर पड़ी और मुगल साम्राज्य का पतन आरम्भ हो गया वहीं दूसरी ओर स्थानीय शासकों में भी संघर्ष आरम्भ हो गया। इसके बावजूद सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि इस संघर्ष और तनाव के बावजूद राजस्थान में व्यापार और वाणिज्य का महत्वपूर्ण विकास हुआ। इसके पीछे यहाँ के शासकों की व्यापार को प्रोत्साहन देने की नीति कार्य कर रही थी क्योंकि इन शासकों को इस बात का आभास हो गया था कि व्यापार और वाणिज्य के विकास के बिना राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ नहीं किया जा सकता। इसलिए उन्होंने व्यापारियों को विशेष रियायतें दी और राजस्थान के बाहर के व्यापारियों को भी राजस्थान में आकर बसने के लिए प्रेरित किया।

व्यापार प्रोत्साहन की इस नीति और व्यापार के लिए अनुकूल प्रतिस्थितियाँ पाकर आगरा, दिल्ली, गुजरात, मालवा, मुल्तान, लाहौर और यहाँ तक कि कंधार से भी बड़े पैमाने पर व्यापारी राजस्थान में आकर बसे और यहाँ व्यापार एवं वाणिज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।^{xii} वाणिज्य और व्यापार के विकास के लिए अच्छी सड़कों का होना सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। साहित्यिक सत्रोतों से इस बात की पुष्टि होती है कि अनेक प्रमुख व्यापारिक मार्ग राजस्थान को अन्य व्यापारिक नगरों के साथ जोड़ते थे। अब्बास खाँ शेरवानी के विवरण से पता चलता है कि एक प्रमुख मार्ग आगरा से चित्तौड़ और एक अन्य आगरा से जोधपुर को जोड़ता था।^{xiii} अजमेर भी विभिन्न व्यापारिक मार्गों के द्वारा अम्बेर, मेवात, सिवाना, जोधपुर और साम्भर के साथ जुड़ा हुआ था।^{xiv} तारीख-ए-मुबारकशाही के वृत्तान्त के अनुसार एक प्रमुख व्यापारिक मार्ग दिल्ली से मालवा तक जाता था जो कि बयाना से होकर गुजरता था।^{xv} इसी प्रकार हमें तबकात-ए-अकबरी से जानकारी मिलती है कि एक सीधा रास्ता आगरा से माण्डू तक जाता था जो कि रणथम्भौर, कोटा और उज्जैन से जाता था।^{xvi} बाबर के वृत्तान्त से भी हमें आगरा से ग्वालियर तक के एक सीधे मार्ग का पता चलता है।^{xvii} इसी प्रकार तुजुक-ए-जहाँगीरी के आधार पर हमें पता चलता है कि एक प्रमुख व्यापारिक मार्ग अजमेर से मालवा तक जाता था जो कि डसवाली, बालोदा, कानरा और खैराबाद के रास्ते जाता था।^{xviii} इस प्रकार राजस्थान के प्रमुख व्यापारिक नगरों के साथ सीधे सम्बन्ध थे। व्यापार के विकास में एक प्रमुख बाधा ये थी कि इन व्यापारिक मार्गों में से कई काफी असुरक्षित थे। हाड़ौती, मेवाड़, मेवात, मारवाड़ और शेखावटी आदि क्षेत्रों में लुटेरे व्यापारियों को लूट लिया करते थे। इसलिए मुगल शासकों ने इन व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा के लिए विशेष उपाय किए जिसकी पुष्टि समकालीन सत्रोतों से होती है।^{xix} इस प्रकार इन परिस्थितियों में अठारहवीं शताब्दी में राजस्थान क्षेत्र में व्यापार और वाणिज्य का बहुत विकास हुआ।

सन्दर्भ:-

- सतीश चन्द्र, पार्टिज एण्ड पॉलिटिक्स एट द मुगल कोर्ट (1770-1740), ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रैस, नई दिल्ली, 2002
- इरफान हबीब, द अंग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इण्डिया, 1556-1707, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रैस, नई दिल्ली, 2002

- अशिन दास गुप्ता, इण्डियन मर्चेन्ट्स एण्ड द डिक्लाईन ऑफ सूरत: 1700–1750, मनोहर पब्लिकेशन, दिल्ली, 1994
- बी०आर० ग्रोवर, एन इंटीग्रेटेड पैटर्न ऑफ कमर्शियल लाईफ इन द रूरल सोसायटी ऑफ नार्थ इण्डिया डयूरिंग द सेवेंथिं-एटींथ सेंचुरीज, प्रोसीडिंग्स ऑफ इण्डियन हिस्टोरिकल रिकार्ड्स कमीशन, 37 (1966)
- करेन लियोनार्ड, द ग्रेट फर्म थ्योरी ऑफ द डिक्लाईन ऑफ द मुगल अम्पायर, कम्पेयरेटिव स्टडीज इन सोसायटी एण्ड हिस्ट्री, वॉल्यूम-21, 1979, पृ० 151–167
- सी० ए० वैली, रूलर्स, टाउन्समैन एण्ड बाजार्स, नार्थ इण्डियन सोसायटी इन द एज ऑफ ब्रिटिश एक्सपेंशन, 1770–1870 कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रैस, नई दिल्ली, 1988
- एस० सुब्रमण्यम एण्ड सी० ए० बेली, पोर्ट फोलियो कैपीटलिस्ट एण्ड द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ अर्ली मार्टन इण्डिया, आई० ए० एस० एच० आर०, ग्पट न० 4, 1988
- एस० पी० गुप्ता, द अग्रेयियन सिस्टम ऑफ इस्टर्न राजस्थान, ७१६००.७१७५०ए मनोहर पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1986
- दिलबाग सिंह, स्टेट, लैंडलार्ड्स एण्ड पिजेंट्स : राजस्थान इन दा एटिंथ सेंचुरी, मनोहर पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1990
- जी० डी० शर्मा, राजपूत पॉलिटी: ए स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट ऑफ मारवाड, दिल्ली, 1977
- बी० एल० भदानी, पिजेंट्स, आर्टिजन्स एण्ड इंटरप्रीनियर्स : इकोनामी ऑफ मारवाड इन सेवेंथिं सेंचुरी, रावत पब्लिकेशन, जयपुर, 1999
- बी० एल गुप्ता, ट्रेड एण्ड कॉमर्स इन राजस्थान डयूरिंग द एटिंथ सेन्चुरी, जयपुर पब्लिशिंग हाऊस, जयपुर, 1987, पृ० 242
- अब्बास खाँ शेरवानी, तारीख-ए-शेरशाही, इलियट और डाउसन द्वारा अंग्रेजी में अनुवादित, भाग-4, पृ० 141–156
- निजामुद्दीन अहमद, तबकात-ए-अकबरी, बिब० इण्डिका सीरीज, कलकत्ता, 1927, पृ० 335–336
- तारीख-ए-मुबारकशाही, के० के० बसु द्वारा अंग्रेजी में अनुवादित, गायकवाड ओरियंटल सीरीज, 1932, पृ० 166, 193, 217
- निजामुद्दीन अहमद, तबकात-ए-अकबरी, पूर्वोद्धृत, पृ० 211–213
- बाबरनामा (मेमोयर्स ऑफ बाबर), बेवरिज द्वारा अनुवादित, खण्ड-2, लो प्राईस पब्लिकेशन, दिल्ली, 1989, पृ० 577–608
- तुजुक-ए-जहाँगीरी, एलेक्जेंडर रोजर्स और हेनरी बेवरिज द्वारा अनुवादित खण्ड-1, मुँशीराम मनोहरलाल पब्लिशर्स लिमिटेड, रानी झॉंसी रोड, न्यू दिल्ली, थर्ड एडीशन, 1978, पृ० 340–349
- निजामुद्दीन अहमद, तबकात-ए-अकबरी, पूर्वोद्धृत, पृ० 340–342